concentrate plant at Silchar and the cost expected;

(b) the cost incurred till March 1995; and

(c) the present proposals about the future of the company?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) The originally fixed date for commissioning the plant was January, 1986 and the estimated cost was Rs. 207.00 lakhs.

(b) The cost incurred till March, 1995 is Rs. 281.26 lakhs.

(c) It has been decided to dispose of the plant at Silchar on "as is where is" basis.

Preparation for Blue Print for Transport Sector

334. DR. BAPU KALDATE:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI K.M. KHAN:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the World Bank has prepared a blue print for the improvement of the transport sector in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) The World Bank has submitted a report on the long term issues in the Transport Sector in India. The report is a voluminous one covering 91 issues, in various transport sectors viz. Roads, Ports, Shipping, Road Transport, Railways, Civil Aviation and it has been examined in this Ministry. As a preliminary response, although the report has touched on some important issues, we have reservation about some of them. We agree that the various transport modes should develop in an integrated manner within the minimum resource outlay to match the demand for increased transport infrastructure. We realise that lack of transport infrastructure can be a serious constraint for economic growth. With the involvement of private sector utilising private sector funds through privatisation, we expect, we shall be able to meet the infrastructural requirements of the future adequately.

विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

335. श्री विष्णु कान्त शास्त्री: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बाहर स्थित भारत के राजदूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और अन्य कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत वर्ष इनमें से किन-किन राजदूतावासों और अन्य कार्यालयों में गत वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को हिन्दी में पढ़ा गया और वहां के अधिकारियों ने अपने-अपने भाषण हिन्दी में दिए; और

(ग) इन अवसरों पर हिन्दी की उपेक्षा होते रहने के क्या कारण हैं और राष्ट्रीय महत्व के इन समारोहों में हिन्दी के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) भारत के 84 राजदूतावास, 27 हाई कमीशन, 27 प्रधान कौंसलावास, 2 कमीशन, 3 सहायक हाई कमीशन, 5 विशिष्ट मिशन हैं। ये कार्यालय विदेश मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन आते हैं। अन्य मंत्रालयों और विभागों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों की निश्चित संख्या का पता लगाया जा रहा है तथा सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) गणतन्त्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के भाषणों को केवल विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों को भेजा जाता है। भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है वे मिशन/केन्द्र में आयोजित गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस समारोहों में भाग लें।

गणतन्त्र दिवस 1994 और स्वाधीनता दिवस 1994 के दौरान, राष्ट्रपति के संदेश 35 मिशनों/केन्द्रों में हिन्दी में 45 मिशनों/केन्द्रों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में मिश्रित रूप से और 39 मिशनों/केन्द्रों में अंग्रेजी में पढ़े गए। शेष मिशनों/केन्द्रों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मंत्रालय ने लिखित रूप से यह सलाह दी है कि समारोह के अवसरों पर, विशेषरूप से गणतन्त्र दिवस और स्वाधीनता दिवस समारोहों पर हमारे मिशनों/केन्द्रों में हिन्दी के उपयोग के बढ़ावा दिया जाए। इन समारोहों पर हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हो रही है।

Fencing Work at Indo-Bangaldesh Border

336. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the fencing work through barbed wire at Indo-Bangladesh border has been interrupted due to heavy protest by the Bengladesh nationals and security forces; and

(b) if so, what are the details of the measures which have been taken to check it and start the work there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) and (b) A protest was received from 15 Bn. Bangladesh Rifles conveying concern about erection of fencing which will effect the movement of Bangladesh nationals to 33 Bangladesh enclaves in India opposite District Lalmonirhat. The matter was discussed during DG level Coordination Meeting held from 26 to 30 June, 1995 between Bangladesh Rifles and BSF authorities. The fencing work is in progress.

केले से तैयार की गई खाद्य वस्तुओं का विकास और निर्यात किया जाना

337 श्री नरेश यादव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केले के उत्पादन में वृद्धि करने और केले से तैयार खाद्य-वस्तुओं के विकास और निर्यात के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) क्या सरकार केले के उत्पादन में वृद्धि करने और केला उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई सेमिनार आयोजित करने पर विचार कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) सरकार विभिन्न बागवानी उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है जिनमें केला और केले से बने उत्पाद शामिल हैं।

(ख) इस मंत्रालय में बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस मंत्रालय का इस संबंध में कोई सेमिनार आयोजित करने का विचार नहीं है। बहरहाल, बागवानी तथा बागवानी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, उद्योग संघों को सेमिनार आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

"Forest Fires in the Country"

338. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the country witnessed a large number of forest fires in the last few months;

(b) what is the estimated loss of forest wealth due to these fires; and

(c) what measures are being taken to remove the administrative and infrastructural difficulties encountered in dealing with the problem?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected from the States/Union Territories and will be laid on the table of the House.

(c) A Centrally Sponsored Scheme namely 'Modern Forest Fire Control Mathods' is under implementation in 11 states of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamilnadu and Uttar Pradesh.